



भारत का राजपत्र The Gazette of India

CH
1-8-85

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रामाणिकर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 1985/माघ 19, 1985

No. 70]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1985/MAGHA 19, 1985

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह खण्ड संकलन से अलग हो सके
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1985

का. आ. 104 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 641 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड फाइटोकीमिकल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाऊस, (दूसरी मंजिल), एक और तीन, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स डा. पाल लोहमान (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 793 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1981, सं. का. आ. 312 (अ),

1544 GI/84

तारीख 8 मई, 1982, का. आ. 789 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982, का. आ. 801 (अ), तारीख 10 नवम्बर, 1983, का. आ. 364 (अ), तारीख 8 मई, 1984, का. आ. 825 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1984, और का. आ. 926 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-बक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 8 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः वर्ष और तीन मास की अवधि के लिए करते रहने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त छः वर्ष और तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करता रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18-बक की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उसमें ऐसे प्रबन्ध को छ मास की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की थी ;

और, उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश तारीख 7 फरवरी, 1985 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक

(1)

उपक्रम का प्रबन्ध छः मास की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18-एक की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश तारीख 8 अगस्त, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(2)/80-सी. यू. एस.]

पी. मुरारी, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY
AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1985.

S.O. 104(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O.641 (E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House, (2nd Floor), 1 and 3, Brabourne Road, Calcutta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of three years commencing on the 10th November, 1978 ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of

Industrial Development) No. S.O. 793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O.789(E), dated the 9th November, 1982, S.O.801(E), dated the 10th November, 1983, S.O. 364(E), dated the 8th May, 1984, S.O.825(E), dated the 9th November, 1984, and S.O.926(E), dated the 7th December, 1984, the Central Government, with the permission of the High Court at Calcutta, under section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of six years and three months, upto and inclusive of the 8th February, 1985;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of six years and three months, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months ;

And, whereas, the said High Court, by its Order dated the 7th February, 1985, permitted the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 8th August, 1985.

[File No. 4(2)/80-Cus]

P. MURARI, Additional Secy.